नोएडा संस्करण
वर्ष-11, अंक -337
रविवार, 30 मई, 2021
पृष्ठ 12
मूल्य 3 रु*
नोएडा, लखनऊ, झांसी और देहरादून से प्रकाशित

दैनिक भास्कर

देश का सबसे विश्वसनीय अखबार

For epaper → www.updainikbhaskar.com

06 सफल और सार्थक जीवन की शक्ति ... "ना"

जिंदगी / वैक्सीन यूफ्लेक्स कम्पनी के नोएडा में कार्यरत 6000 कर्मचारियों को निःशुल्क वैक्सीन लगाने के कार्य का शुभारम्भ

यूफ्लेक्स के चेयरमैन ने सबसे पहले वैक्सीन लगवाकर दिया संदेश

भास्कर विशेष

नोएडा। शनिवार का दिन इतिहास में इसलिए भी दर्ज रहेगा, क्योंकि यूफ्लेक्स कम्पनी ने नोएडा में कार्यरत अपने 6000 कर्मचारियों को निःशुल्क वैक्सीन लगाने का कार्य कैलाश अस्पताल के अनुभवी डॉक्टरों की टीम के साथ आरंभ कर दिया है।

श्री अशोक चतुर्वेदी, चेयरमैन ऐंड मैनेजिंग डायरेक्टर, यूफ्लेक्स लिमिटेड ने सबसे पहले टीका लगवाकर देश की अवाम को यह संदेश दिया कि वैक्सीन लगवाना निहायत जरूरी है। इस संदेश की मुख्य बात ये ही है कि यूफ्लेक्स ग्रुप के सभी कर्मचारी वैक्सीन लगवाकर न केवल अपने परिवार को, बल्कि देश के सभी लोगों को सुरक्षित रखें। श्री अशोक चतुर्वेदी के साथ ही दैनिक भास्कर के प्रधान संपादक दीपक द्विवेदी ने भी वैक्सीन का टीका लगवाया। इसके बाद उन्होंने कहा, दो गज की दूरी, मॉस्क है जरूरी। उन्होंने कहा, खाली वैक्सीन लगाने से ही नहीं होगा, हमें पीएम मोदी के गाइडलाइंस को भी फॉलो करना होगा ... दो गज की दूरी, मॉस्क है जरूरी। दीपक जी ने इसलिए कहा, क्योंकि मॉस्क और दो गज दूरी ही लोगों को कोरोना वायरस से बचा सकती है।

आज कोरोनाकाल में जहां एक ओर ज्यादातर कंपनियों में कर्मचारियों की छंटनी हो रही है, कहीं वेतन काटे जा रहे हैं, तो कहीं काम का बोझ बढ़ा दिया जा रहा है, वहीं यूफ्लेक्स कम्पनी के चेयरमैन कोविड काल में सभी कर्मचारियों को निःशुल्क कोविड मेडिसिन उपलब्ध करवा रहे हैं, जो कि समाज के लिए एक मैसेज है। गीता में ये ही लिखा हुआ है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। वही काम आज चतुर्वेदी जी कर रहे हैं। कम्पनी ने न केवल अपने कर्मचारियों के लिए वेन्टिलेटर, ऑक्सीजन कन्सन्ट्रेटर व ऑक्सीजन सिलेंडर काफी मात्रा में खरीदे हैं, बल्कि सभी कर्मचारियों को उनकी जरूरत के अनुसार घर में इलाज के लिए सुविधाएं भी मुहैया करवाई हैं, ताकि सभी कर्मचारियों को उनकी जरूरत के अनुसार घर में ही इलाज के लिए सब कुछ आसानी से उपलब्ध हो जाए। केवल ये ही नहीं, यूफ्लेक्स कम्पनी ने कई टन ऑक्सीजन भी अस्पतालों और नोएडा जिलाधिकारी को उपलब्ध करवाई है। कम्पनी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर और भी जरूरत की सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने को तैयार हैं। इस मुसीबत की बेला में यूफ्लेक्स पूरी तन्मयता से देश के साथ खड़ा है। नोएडा का पहला ऐसा संस्थान है, जो अपने कर्मचारियों का न केवल टीकाकरण करा रहा है, बल्कि जनजागरण का काम वर्षों से बखूबी करता आ रहा है। गौरतलब है कि वैक्सीनेशन का यह सिलसिला कम्पनी में 29 मई 2021 से 5 जून 2021 तक चलेगा। कम्पनी ने एक छोटा ऑक्सीजन प्लांट भी अपनी फैक्ट्री में लगाने का कार्य शुरू कर दिया है। दिनेश जैन, जो कि यूफ्लेक्स लिमिटेड के अध्यक्ष हैं और कानूनी और कॉर्पोरेट मामले के सर्वेसर्वा हैं, उन्होंने ये जानकारी दी।

पीएम मोदी 1 मार्च को एम्स में टीका लगवाया।

टीका लगवाने के बाद मोदी ने कहा था आइए, हम सब साथ मिलकर भारत को कोरोना मुक्त बनाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में COVID-19 वैक्सीन की अपनी पहली खुराक ली। ट्विट करके कहा, हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने कोरोना महामारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम किया है। मैं उन सभी से अपील करता हूं, जो वैक्सीन लेने के लिए योग्य हैं, वे इसे जरूर लें।

यूफ्लेक्स के चेयरमैन अशोक चतुर्वेदी ने सबसे पहले वैक्सीन लगवाया।

यूफ्लेक्स ने मानवता की दृष्टि से अपने ही खर्चे पर 6000 कर्मचारियों को टीका लगवाया और **peon to president** की परिभाषा को चरितार्थ कर दिया। प्रधानमंत्री की सोच और विजन को आगे बढ़ाते हुए यूफ्लेक्स के चेयरमैन ने एक अद्भुत और अतुलनीय कार्य करने का बीड़ा उठाया है। इससे समाज में अच्छा संदेश जाएगा।

दैनिक भास्कर के प्रधान संपादक ने टीका लगवाया।

- दैनिक भास्कर के प्रधान संपादक दीपक द्विवेदी ने भी टीका लगवाया
- कहा - 'दो गज की दूरी, मॉस्क है जरूरी' का नियम सभी पालन करें
- घर में इलाज के लिए सुविधाएं भी मुहैया करा रही 'यूफ्लेक्स'

कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की पीएम केयर्स से मदद करेंगे मोदी

नई दिल्ली, भास्कर न्यूज। कोरोना वायरस महामारी की वजह से अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आए हैं और पीएम केयर फंड से कई योजनाओं का ऐलान किया है। कोरोना से अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों की शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक में मोदी सरकार मदद करेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है कि कोरोना महामारी में माता-पिता गंवाने वाले बच्चों की 'पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन' योजना के तहत मदद की जाएगी। सरकार की ओर से अनाथ बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और उनका हेल्थ बीमा भी किया जाएगा।

- मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और हेल्थ बीमा भी किया जाएगा
- बच्चों को 18 वर्ष होने पर मासिक भत्ता दिया जाएगा
- 23 वर्ष होने पर पीएम केयर्स फंड से 10 लाख रुपये दिए जाएंगे

पीएमओ ने कहा कि कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों को 18 वर्ष होने पर मासिक भत्ता दिया जाएगा और 23 वर्ष होने पर पीएम केयर्स फंड से 10 लाख रुपये दिए जाएंगे। उनकी मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। पीएमओ ने कहा कि कोरोना की वजह से अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों को 18 साल की अवधि तक पांच लाख का मुफ्त हेल्थ बीमा भी मिलेगा। साथ ही ऐसे बच्चों की उच्छ शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन दिलाने में मदद की जाएगी और इसका ब्याज पीएम केयर्स फंड से वहन किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बच्चे भारत के भविष्य हैं और हम उनकी सुरक्षा और सहायता के लिए सबकुछ करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि समाज के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों की देखभाल करें और एक उज्ज्वल भविष्य की आशा करें। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने भारत के लिए कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी। रोज लाखों मामले सामने तो आए ही, अब तक तीन लाख से अधिक लोगों की जान भी जा चुकी है।

कोरोना के मामले घटे, दिल्ली के बाद यूपी में कर्फ्यू में आंशिक ढील

अब अनलॉक हो रहा देश

भास्कर न्यूज

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में अगर नए मामलों की संख्या में गिरावट जारी रहती है तो शहर में ज्यादा गतिविधियों को मंजूरी दी जाएगी, ताकि आर्थिक गतिविधियां पटरी पर लौट आए।

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का असर अब धीरे-धीरे कम हो रहा है। देश में अब कोरोना के रोजाना मामले 2 लाख से नीचे आ गए हैं। ऐसे में कई राज्य अब कोरोना की सख्त पाबंदियों में ढील देने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली, यूपी समेत देश के कई राज्यों में एक महीने से भी ज्यादा समय से लॉकडाउन लागू है। इस बीच दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों ने संकेत दिया है कि वे 1 जून से लॉकडाउन में छूट दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही पंजाब, राजस्थान समेत कई राज्य ऐसे भी हैं, जहां लॉकडाउन को जून के पहले हफ्ते से आगे बढ़ा दिया गया है।

दिल्ली 31 मई से 'अनलॉक'

दिल्ली में 31 मई से अनलॉक शुरू होने जा रहा है। दिल्ली में फिलहाल 31 मई सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन है। इस बीच शुक्रवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि कोविड-19 के केस में कमी जारी रहती है तो 31 मई से चरणबद्ध तरीके से 'अनलॉक' की प्रक्रिया शुरू होगी। दिल्ली में 20 अप्रैल को पहली बार लॉकडाउन लगा था। इसके बाद कोरोना के लगातार बढ़ते केस को देखते हुए हफ्ते दर हफ्ते इसे आगे बढ़ाया गया।

उत्तर प्रदेश में आंशिक ढील

कोरोना वायरस संक्रमण में सेकेंड स्ट्रेन के बढ़ते मामलों के कारण एक मई से प्रदेश में लागू कोरोना कर्फ्यू में एक जून से आंशिक ढील दी जाएगी। इस दौरान अधिक ऐक्टिव केस वाले जिलों में राहत नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश में सभी जगह 33 प्रतिशत उपस्थिति के साथ सरकारी तथा प्राइवेट कार्यालय भी खोले जाएंगे। प्रदेश में नाइट कर्फ्यू फिलहाल लागू रहेगा। इसमें रात आठ बजे से अगले दिन सुबह सात बजे तक तमाम पाबंदियां जारी रहेंगी।

मध्यप्रदेश में भी मिलेगी छूट

मध्यप्रदेश में कोरोना अब काबू में आ रहा है। तीसरी लहर की आशंका की वजह से शिवराज सरकार ने 1 जून से धीरे-धीरे अनलॉक करने की तैयार कर ली है। इसके लिए गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूहों ने अनलॉक को लेकर सरकार से सिफारिशें की हैं। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर खोलने के लिए भी मंत्री समूह का गठन किया गया है। यह जल्दी ही बैठक कर अपनी सिफारिशें सरकार को भेजेगा। मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू की पाबंदियों में 1 जून से धीरे-धीरे ढील दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दुनिया को आगे बढ़ना है, लेकिन हमें इस तरह से अनलॉक करना है कि कोरोना फिर से नहीं फैले।

महाराष्ट्र में पाबंदियों में कमी

महाराष्ट्र ने 14 अप्रैल को 15 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया था और ये लॉकडाउन फिलहाल 1 जून तक प्रभावी है। कोरोना लॉकडाउन को लेकर महाराष्ट्र फैसला ले सकता है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि जहां मामले कम हो रहे हैं, वहां अगले कुछ दिनों में पाबंदियों में कमी को लेकर गाइडलाइंस जारी की जाएगी।

बिहार-झारखंड ने भी दिए संकेत

बिहार में भी 1 जून से लॉकडाउन में ढील के संकेत दिए गए हैं। झारखंड में कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट आई है।

-शेष पेज 10 पर

केंद्र की लापरवाही के चलते ऑक्सीजन का संकट : प्रियंका

नई दिल्ली, भास्कर न्यूज। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के लिए केंद्र सरकार की 'लापरवाही' को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने शनिवार को कहा कि अगर केंद्र ने पहली एवं दूसरी लहर के बीच मिले समय में योजनाबद्ध ढंग से तैयारी की होती तो इस संकट को टाला जा सकता था। सरकार से प्रश्न पूछने की अपनी श्रृंखला 'जिम्मेदार कौन' के तहत उन्होंने फेसबुक पोस्ट के जरिए यह सवाल किया कि केंद्र ने महामारी वाले साल 2020 में ऑक्सीजन का निर्यात 700 प्रतिशत तक क्यों बढ़ा दिया? उन्होंने यह भी पूछा कि मोदी सरकार ने अपने ही विशेषाधिकार प्राप्त समूह की ऑक्सीजन संकट की सलाह को दरकिनार क्यों किया? कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी ने कहा, 'महामारी की मार के पहले तक ऑक्सीजन को प्राथमिक रूप से औद्योगिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए भारत के पास ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाले विशेष रूप से बनाये गए।

शिष्टाचार के नाते पीएम से मिली थी : ममता

भास्कर न्यूज

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को बंगाल यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की यास तूफान से हुए नुकसान की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक में शामिल नहीं होने को लेकर सफाई दी। पश्चिम बंगाल की सीएम ने कहा कि दरअसल यह बैठक पीएम-सीएम की नहीं थी। वह तो पीएम मोदी बंगाल आए, इसलिए सौजन्यवश और शिष्टाचार के नाते उनसे मिलने गई थी। ममता ने सवाल किया कि इस बैठक में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का क्या काम था? मुझे किसी केंद्रीय मंत्री के इस बैठक में होने पर कोई आपत्ति नहीं। बल्कि पीएम की सुरक्षा में लगी एसपीजी ने मुझे एक घंटे रुकने के लिए कहा था। बनर्जी ने पीएम नरेंद्र मोदी की मीटिंग में 30 मिनट लेट पहुंचने और कागजात देकर निकल जाने के आरोप का भी जवाब दिया। शनिवार को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह स्पष्टीकरण दिया। ममता ने बताया कि पीएम से मुलाकात के पहले क्या हुआ? ममता ने इसका भी जवाब दिया कि क्यों उन्होंने पीएम मोदी को रिसीव नहीं किया? ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है कि हर बार सीएम, पीएम को रिसीव करे।

केंद्र में बुलाए गए बंगाल के मुख्य सचिव

नई दिल्ली/कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय को सेवा विस्तार दिए जाने के मात्र चार दिन बाद केंद्र ने शुक्रवार रात उनकी सेवाएं मांगी और राज्य सरकार से कहा कि वह अधिकारी को तुरंत कार्यमुक्त करे। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने इस कदम को 'जबरन प्रतिनियुक्ति' करार दिया।